

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 31/2013/जयपुर

मैसर्स एच टी सी डीजल इन्जन प्रा.लि.  
मुम्बई

अपीलार्थी

बनाम  
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट तृतीय, वृत तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.सी.अग्रवाल  
सी.ए.  
श्री एन.के.बैद  
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

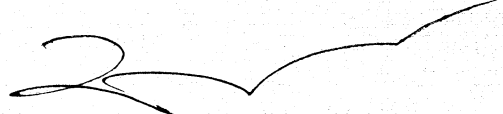
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 7.4.2015

संशोधन आदेश

यह संशोधन पत्र अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (जिसे पुराना अधिनियम कहा जायेगा) की 37 के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1713/2010/जयपुर में पारित निर्णय यद्विनांक 21.12.2012 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03-01.2002 को ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान डीजल इंजिन वेरावल से आयातित करना पाया गया। जांच पर अपीलार्थी कम्पनी के जयपुर के स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा गुजरात (वेरावल) स्थिति फैक्ट्री से डीजल इंजन आयात किये गये थे। कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माल के आर्डर प्राप्त कर माल मंगवाया जाता है तथा ट्रांसपोर्ट कम्पनी से डिलीवरी लेकर ग्राहकों को भुगतान प्राप्त होने के पश्चात सुपुर्द किया जाता है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड तृतीय, वृत तृतीय, करापवंचन, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उक्त प्रकार से राज्य में की गई बिक्री को अविधिक रूप से अन्तर्राज्यीय विक्रय के रूप में प्रदर्शित कर करापवंचन किया जाना मानते हुए माल को बोगस प्रपत्रों में गलत तथ्य अंकित कर मंगाया जाने से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (2) के उल्लंघन के कारण 10 डीजल इंजन कीमतन रु. 2,17,000/-पर कर रु. 17,360/-, सरचार्ज रु. 2,604/- एवं अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 65,100/- आरोपित की। उक्त कर, सरचार्ज एवं शास्ति को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2010 पारित कर अपील अस्वीकार कर आरोपित कर, सरचार्ज एवं शास्ति को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.03.2010 के विरुद्ध कर बोर्ड में अपील करने पर, कर



बोर्ड की एकलपीठ द्वारा उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 21.12.2012 को करते हुए अपील अस्वीकार की गई,जिसमें संशोधन हेतु यह संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा अपीलार्थी की अपील में निर्णय पारित करते समय अधिनियम की धारा 78 (5) के क्षेत्र (scope) पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपील का निस्तारण करते समय ट्रान्जक्शन को भी देखा जाना चाहिए था। उनका कथन है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील संख्या 1713 /2010/जयपुर के ग्राउण्डस आफ अपील के पैरा संख्या 6 में मैसर्स कोरोन बिजनेस सिस्टम लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी जो 2002(28)टैक्स वर्ल्ड 270(डीबी) में प्रकाशित है,की प्रति प्रस्तुत की थी,जिस पर विचार किये बिना ही निर्णय दिनांक 21.12.2012 पारित किया गया है,जो संशोधनीय है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त एवं रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त निर्णय दिनांक 21.12.2012 पारित किया गया है,जो संशोधन योग्य नहीं है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किये जाने का प्रावधान है, जो रेकार्ड से परिलिखित होती हों। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में बहस के दौरान ऐसी किसी भूल का उल्लेख नहीं किया गया है,जो रिकार्ड से परिलिखित होती है,इसलिए संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा निर्णय दिनांक 21.12.2012 पर मनन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी का मुख्य तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 78 (5) के क्षेत्र (scope) पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपील का निस्तारण करते समय ट्रान्जक्शन को भी देखा जाना चाहिए था। उनका कथन है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील संख्या 1713 /2010/जयपुर के ग्राउण्डस आफ अपील के पैरा संख्या 6 में मैसर्स कोरोन

बिजनेस सिस्टम लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी जो 2002(28)टैक्स वर्ल्ड 270(डीबी) में प्रकाशित है,की प्रति प्रस्तुत की थी,जिस पर विचार किये बिना ही निर्णय दिनांक 21.12.2012 पारित किया गया है, सही एवं उचित नहीं है क्योंकि निर्णय दिनांक 21.12.2012 के पेज 3 के पैरा प्रथम में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि " उभय पक्षों की बहस सुनी गयी,उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रोद्धरित निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया।" मूल अपील संख्या 1713/2010/जयपुर के सुनवाई के समय प्रस्तुत बहस, उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों, अपीलीय अधिकारी के आदेश में अंकित न्यायिक दृष्टान्तों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात एवं प्रकरण तथ्यों के पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 21.12.2012 पारित किया गया है। निर्णय दिनांक 21.12.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय दिनांक 21.12.2012 पारित किया गया है। कर बोर्ड की एकलपीठ पारित द्वारा निर्णय दिनांक 21.12.2012 में रिकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरणों के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है। अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जा सकता है, जो बिना वाद-विवाद के रिकार्ड से परिलक्षित होती हो। निर्णय दिनांक 21.12.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रिकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) के प्रकरण में मत प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

***"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.***

***In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification***

*as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-*

*“8.The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.*

*An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf.”*

*In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held thagt such a power of rectification could onlybe exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the context of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.*

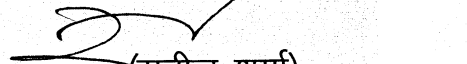
*Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the*

*present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नहीं जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य